"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2004—फाल्गुन 15, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

क्रमांक ई 1-16/2003/1/2.—श्री एम. एस. पैकरा, भा.प्र.से. (1991) कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री कृष्ण राम पिस्दा, भा.प्र.से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री मनोज कुमार त्यागी, भा.प्र.से., मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (भा. प्र. से. कक्ष-2) का कार्य भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक ई 1-6/2003/1/2.—श्री एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. (1979) को प्रमुख सचिव वेतनमान रु. 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव के वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक एफ ए 4-10/2003/1/एक.—माननीय श्री एल. सी. भादू, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 8-12-2003 से 12-12-2003 (5 दिवस) तक का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें अवकाश के पूर्व दिनांक 7-12-2003 एवं पश्चात् दिनांक 13-14 दिसंबर 2003 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक एफ ए 4-13/2002/1/एक.—मा. श्री फखरुद्दीन, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 22-11-2003 से 28-11-2003 (7 दिवस) तक का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 29 एवं 30 नवंबर, 2003 तथा 1 दिसम्बर, 2003 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक 14/831/2003/1-8.—श्री आर. पी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 8-12-2003 से 12-12-2003 तक कुल 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही उन्हें दिनांक 13 एवं 14-12-2003 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री वर्मा को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा को पुनः अवर सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक 16/885/2004/1-8.—श्री के. के. बाजपेयी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 21-1-2004 से 29-1-2004 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री बाजपेयी के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग देखेंगी.

3. अवकाश अवधि में श्री बाजपेयी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. अवकाश से लौटने पर श्री बाजपेयी को पुनः सामान्य प्रशासम विभाग में पदस्थ किया जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाजपेयी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2004

क्रमांक 381/138/2004/स.प्र.वि./1/2/लीव.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2646/2166/2003/1/2/लीव, दिनांक 24-12-2003 द्वारा श्री एम. के राऊत, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26-12-2003 से 6-1-2004 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में दिनांक 7-1-2004 को 1 दिवस का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त आदेश दिनांक 24-12-2003 में उल्लेखित कंडिका (2) से (4) यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2004

क्रमांक 390/154/2004/स.प्र.वि./1/2/लीव.—श्री अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, बारहवां वित्त आयोग एवं संस्थागत वित्त को दिनांक 7-1-2004 से 20-1-2004 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, बारहवां वित्त आयोग एवं संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 401/191/2004/2/लीव.—श्री एम. आर. ठाकुर, सचिव, लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 9-12-2003 से 23-1-2004 तक (30 दिवस) का लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. ठाकुर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, लोक आयोग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में, श्री एम. आर. ठाकुर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि, श्री एम. आर. ठाकुर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 403/166/2004/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री उजागरसिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर को दिनांक 8-1-2004 से 16-1-2004 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18-1-2004 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उजागरसिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में, श्री उजागरसिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि, श्री उजागरसिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2004

क्रमांक 146/1563/जेल/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय जेल, जिला जेल एवं उप जेलों में नियुक्त किये गये अशासकीय संदर्शकों को जेल नियमावली की कंडिका 815 (6) उप नियम 2 में दिये गये प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 1-19/खाद्य/2001/29.—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 के अध्याय तीन की कंडिका 20 (2) के तहत राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय श्री मेघाराम साहू, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 517/223/व्हीआईपी./2004/अंत्या.वि.वि.नि.—राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 4557/223/आजाक/2003 रायपुर, दिनांक 15-9-2003 द्वारा छत्तीसगढ़ हज कमेटी एक्ट 1992 की धारा 17 सहपठित धारा 18 के खण्ड 1 (ब) के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के विधान सभा सदस्य के रूप में श्री बदरूद्दीन कुरैशी को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया था. श्री कुरैशी के वर्तमान में विधान सभा सदस्य नहीं होने के कारण श्री कुरैशी की हज कमेटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, विशेष सचिव.

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2004

क्रमांक एच/7021/ज.सं.सं./04.—क्रमांक एच-1177/2001/जसं/2004 राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल, 2001 छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक अंतिम नियम दिनांक 27 अप्रैल, 2001 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम-चार के अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के लिये निम्नानुसार समिति गठित करता है :—

(1) श्री प्रदीप कुमार, संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर
(2) श्री अनल प्रकाश शुक्ल, संपादक, दैनिक नवभारत, रायपुर
(3) श्री प्रदीप मोईत्रा, ब्यूरो चीफ, हिन्दुस्तान टाइम्स
(4) श्री रूचिर गर्ग, ब्यूरो चीफ, सहारा समय
(5) श्री सुशील कोठारी, संपादक, सबेरा संकेत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 18-01/2000/नौ/17.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2794/298/2000/स्वा., दिनांक 25-6-2001 तथा अधिसूचना क्रमांक 61/298/2000/स्वा.,दिनांक 4-1-2002 द्वारा गठित "राजीव जीवन रेखा कोष" का नाम परिवर्तित करते हुये उसके स्थान पर "संजीवनी कोष" स्थापित करता है तथा तत्संबंधी नियमों को निम्नानुसार संशोधित करता है :—

1. कोष से सहायता राशि की पात्रता केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की सूची में शामिल व्यक्तियों को होगी. विशेष परिस्थितियों में इस नियम को शिथिल करने का अधिकार मान. मुख्यमंत्री जी को होगा.

2. कोष से सहायता की अधिकतम सीमा रुपये 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) होगी. विशेष परिस्थितियों में मान. मुख्यमंत्री जी को इस नियम को भी शिथिल करने का अधिकार होगा.

3. कोष से सहायता केवल शासकीय अस्पतालों अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज के लिये दी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार ध्रुव, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-70/03/उ.शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 (3) के अधीन बी. एल. एस. यूनिवर्सिटी, रायपुर के कुलपति द्वारा धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत अध्यादेशों को सहमति प्रदान करती है तथा छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 की उपधारा (4) द्वारा 05 (पांच) "प्रथम अध्यादेशों" को अनुमोदित करती है.

ये अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

ORDINANCE NO. – 1

Admission of Students of the University and their enrolment
(Section 27 (1) (a) of the Adhiniyam)

1. In this Ordinance unless there is anything contrary to Statute and the Adhiniyam

(a) "Qualifying examination" means an examination the passing of which makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelors, Masters, M. Phil. Doctorate Degrees or diplomas, Certificates conferrable by the University.

(b) 'Compartment' or 'Supplementary' means a result in which a student has been declared fail in ONE subject by the concerned examining body i.e. a recognized Board of Secondary Education e.g. CBSE, ICSE, State Board of Secondary Education, etc. Such a student may be declared pass if he/she secures required percentage of marks in the examination held subsequently by the same examining body and declared Pass.

(c) "Equivalent examination" means an examination conducted by

(i) Any recognized Board of Secondary Education or

(ii) Any Indian or Foreign University or awarding body recognized by this University.

(d) 'Gap period' means the period between the last date of attending the educational institution (excluding coaching institutes) and the date of taking the admission in the University.

2. The student seeking admission to the Pass/Hons. Degree/ Diploma courses of the University or schools/college institutes recognized and/or affiliated to the University and the Study Centers shall submit the application on prescribed form on or before last of submission of such form, along with necessary certificates.

3. The admission committee will screen the applications and eligible candidates will be awarded provisional admission. An entrance test for admission may be prescribed for certain courses by the Academic Council.

4. Admission will be offered twice in an academic year viz. autumn session and spring session or as prescribed by the Academic Council.

5. The Student shall within a month of his admission submit certified copies of (I) character certificate from the Principal of the school/ college last attended (ii) Evidence of the Date of Birth (iii) statement of marks of the qualifying examinations (iv) Medical certificate certifying physical fitness (v) Transfer Certificate and Migration certificate, wherever applicable. The admission is

subject to the submission of these certified documents. If any of these are found to be forged, tampered or false, the student's admission will automatically stand cancelled.

6. A student who has passed a part of any degree or diploma from another University/ awarding body shall be admitted to subsequent higher class for such examination in any institution / center after its equivalence has been determined by the Academic Council.

7. A student with " Compartment/ Supplementary' result may be granted 'Provisional' admission to any of the curses of study to which he / she would have otherwise normally been admitted if he / she had secured clear Pass grades.

Provided that a provisionally admitted student submits the statement of Marks after passing in the qualifying examination but before the declaration of Ist semester University results, his/her result will not be withheld.

Provided that a student admitted student provisionally fails to pass in the qualifying examination, his/her admission shall be terminated irrespective of the results in the University examination and the fee paid shall not be refunded.

8. A student who wished to be admitted after a gap period of one year and more shall along with his application for admission submit and affidavit duly Notarized, justifying the reasons of gap period and certifying that he/she had not taken admission in any other college and had not been rusticated or had not been sentenced to jail for a criminal offence.

9. A person who is under sentence of rustication or has been disqualified from appearing in an examination by any other University/Institution will not be admitted to any course of study in this University and its institutions / centers during the period of rustication or disqualification.

10. The admission of the students shall be completed within a month of commencement of each semester every year or the date decided by the Academic Council.

Provided that where the dates specified or the dates decided by the Academic Council as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day will be the last day of admission.

Provided further that the vice-chancellor shall have the powers to grant admission in cases of genuine hardship beyond the last date of admission as given above on the clear understanding that the attendance of all such students shall be counted from the date of commencement of the course.

11. The Student shall get automatically enrolled as a member of the University as soon as he / she is admitted and pays all the dues together with the prescribed fee for enrolment and submits migration certificate, wherever required.

ORDINANCE NO. – 2

Board of studies

(Section 27 (I) (b) of the Adhiniyam)

1. There shall be a 'Board of Studies' for every course or group of courses as decided by the Academic Council.

2. (I) Each Board shall consist of the following members nominated by the Vice-Chancellor –

(i) Professor(s) of the University Schools/ Colleges/ Study Centres of the specified subject or group of subjects.

(ii) One Associate Professor of the University School/College/Study Centre of the specified subject or group of subjects.

(iii) Any two teachers teaching the said subject(s) at the Study/Academic Centers of the University.

Provided that if the Board is constituted for a group of subjects, adequate

care shall be taken to nominate members under Para 2 (ii) and 2 (iii) above such that all the subjects of the group get represented.

(iv) The Board may co-opt two experts of the subject from outside the University. In case the Board is constituted for a group of subjects, the school may co-opt one expert for each subject such that the number of co-opted members equals the number of subjects for which the Board is constituted.

(2) The Chairman of the Board shall be nominated by the Vice-Chancellor from among the Professor(s) of the University Schools/Colleges of the specific subject or the group of subjects.

If there is no member under clause 2(I) (i), the Chairman may be nominated from among the members of clause 2 (I)(ii) and if no member exists even under this clause, the Chairman shall be nominated from among the members under clause 2(I) (iii) above.

(3) The term of Board shall be two years –

3. Each Board shall lay down the detailed curriculum for the subject leading to the award of the certificates, diplomas and degrees.

4. The curriculum shall be forward looking, student centric and shall be so framed that it clearly lays down the 'learning outcomes', which every student must attain. It shall focus on imparting not only the knowledge and concepts but skills and competencies too. Adequate application oriented exercises and live projects shall constitute the syllabus.

5. It shall identify the Text/ Reference Books, Journals, websites, CD-ROMS, Case History, etc. Which will enhance the learning standards of the student.

6. The academic Council shall lay down the subjects that a student shall study leading to the award of certificates, diplomas and degrees by the University.

ORDINANCE NO. –3

The Award of Degrees, Diplomas, Certificates and Other Academic Distinctions
(Section (27)(I) (c) of the Adhiniyam)

1. The candidate after passing the examination prescribed for a particular certificate, diploma or degree shall become eligible for the award of said certificate, diploma or degree respectively, as the case may be.

2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of certificate, diploma or degree before the Academic Council soon after the declaration of the results. On being approved by the Academic Council, the Certificate and Diplomas shall be issued to the respective candidates by the Registrar.

3. The Certificates and Diplomas shall be signed by the Registrar.

4. The Approval accorded by the Academic Council for the award of the respective degrees shall be placed before the Board of Management for its concurrence. On being concurred by the Board of Management, the degree shall be awarded to the successful candidates at a convocation.

   Provided that if the candidate is in urgent need of the degree and the convocation is likely to be delayed, the degree may be given to him/her by the Vice-Chancellor on the payment of Rs. 1000/- or the fee as may be prescribed by the University from time to time.

5. Degrees/Diplomas requiring approval and permission of specific councils shall be awarded subject to approval by the related regulatory body.

6. The nomenclature of the Degree/ Diploma that would be conferred by the University under different Colleges/ Schools shall be as follows :-

   6.1 School of Arts and Social Sciences (SOARS)

(i)	Bachelor of Arts	B.A.
(ii)	Bachelor of Arts Honours	B.A. (Hons.) subject specific
(iii)	Bachelor of Applied Psychology	
(iv)	Bachelor of Science	B.Sc.
(v)	Bachelor of Science Honours	B.Sc. (Hons) subject specific
(vi)	Bachelor of Education	B. Ed.
(vii)	Bachelor of Library Science	B.Lib.
(viii)	Master of Arts	M.A. subject specific
(ix)	Master of Science	M. Sc. Subject specific
(x)	Master of Education	M.Ed.
(xi)	Master of Philosophy	M. Phil.
(xii)	Master of Library Science	M. Lib.
(xiii)	Doctor of Philosophy	Ph. D.

(xiv)	Doctor of Literature	D.Litt.
(xv)	Diploma in business Communication	
(xvi)	Diploma in Copywriting	
(xvii)	Diploma in Publishing	
(xviii)	Diploma in Writing for Electronic Media	
(xix)	Diploma in Industrial Psychology.	

6.2 School of Law & Public Policy & Administration (SLAPPA)

(i)	Bachelor of Arts & Bachelor of Law (Integrated)	BA LLB (5yrs)
(ii)	Bachelor of Law	LL.B. (3 yrs)
(iii)	Bachelor in Public Policy	BA (PP)
(iv)	Master of Law	LL.M.
(v)	Masters in Public Policy	
(vi)	Masters in Public Governance	
(vii)	Doctor of Philosophy	Ph.D.
(viii)	Doctor of Law	LL.D.
(ix)	Diploma in Administrative law	
(x)	Diploma in business Law	
(xi)	Diploma in Corporate Law & Management	
(xii)	Diploma in Cyber Law & Ethics	
(xiii)	Diploma in Environmental Law	
(xiv)	Diploma in Human Rights Law	
(xv)	Diploma in Intellectual Property Rights Law	
(xvi)	Diploma in Labour Law	
(xvii)	Diploma in Patent Law	

6.3 School of Commerce and Services Management (SCoSeM)

(i)	Bachelor of Commerce	B.Com
(ii)	Bachelor of E-Commerce	B. E-com.
(iii)	Bachelor of Commerce Honours	B. Com (Hons.)

(iv)	Bachelor in Business Process Outsourcing	B.A. (BPO)
(v)	Bachelor in Service Management	
(vi)	Master of Commerce	M. Com.
(vii)	Master of E-Commerce	M. e-Com
(viii)	Master of Philosophy	M. Phil
(ix)	Doctor of Philosophy	Ph.D.
(x)	Doctor of Literature	D. Litt.
(xi)	Diploma in Call Center Management	
(xii)	Diploma in Cost Accounting	
(xiii)	Diploma in Customer Relationship Management	
(xiv)	Diploma in Export Documentation	
(xv)	Diploma in Marketing of Services	
(xvi)	Diploma in Retail Management	
(xvii)	Diploma in Capital Markets of Merchandise Banking	
(xviii)	Diploma in Finance	
(xix)	Diploma in Personnel Management	

6.4 BLS College of Medical Sciences (BCMS)

(i)	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery	M.B.B.S.
(ii)	Master of Surgery	M.S.
(iii)	Master of Medicine	M.D.
(iv)	Doctor of Medicine	D.M.
(v)	Diploma in Science	D.Sc.
(vi)	Diploma in Child Health	D.C.H.
(vii)	Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases	D.T.C.D.
(viii)	Diploma in Ophthalmology Medicine & Surgery	D.O.M.S.
(ix)	Diploma in Chemical Pathology	D.C.P.
(x)	Diploma in Laryngology and Octology	D.I.O.
(xi)	Diploma in Gynecology and Obstetrics	D.G.O

(xii)	Diploma in Orthopedics	D.A.
(xiii)	Diploma in Orthopedics	D. Orth.
(xiv)	Diploma in Public Health	D.P.H.

6.5 School of Engineering Studies & Applied Science (SESAS)

(i)	Bachelor of Technology in Biotechnology	B. Tech (Biotech)
(ii)	Bachelor of Technology in Electronics & Telecommunication Engineering	B. Tech (E & C)
(iii)	Bachelor of Technology in Electronics & Telecommunication Engineering	B. Tech (E & TC)
(iv)	Bachelor of Technology in Civil Engineering	B. Tech (CE)
(iv)	Bachelor of Technology in Civil Engineering	B. Tech (CE)
(v)	Bachelor of Technology in Computer Aided Engineering	B.Tech (CAE)
(vi)	Bachelor of Technology in Electrical & Electronics Engineering	B.Tech (EEE)
(vii)	Bachelor of Technology in Electrical Engineering	B. Tech (EE)
(viii)	Bachelor of Technology in Manufacturing Technology	
(ix)	Bachelor of Technology in Mechanical Design Engineering	B.Tech. (MDE)
(x)	Bachelor of Technology in Mechanical Engineering	B.Tech. (ME)
(xi)	Bachelor of Technology in Mobile Telecommunication Engineering	B. Tech (MTE)
(xii)	Bachelor of Technology in Photonics Engineering	B. Tech (P.E.)
(xiii)	Bachelors of Science	B.Sc.,

(a) Biochemistry

(b) Bioinformatics

(c) Biotechnology

(d) Microbiology

(xiv) Master of Science — M.Sc.

(a) Biochemistry

(b) Bioinformatics

(c) Biotechnology

(d) Microbiology

(xv) Master of Technology — M. Tech

(a) Automotive Engineering & Business

(b) Power Electronics

(c) Communication & Radar Engineering

(d) Power Systems

(e) Embedded System & VLSI

(f) Microelectronics & Communication Systems.

(g) Mobile Networks and Management

(h) Telecom Services Management

(xviii) 5 years Integrated Masters of Technology

(a) Electronics with Telecommunication networks

(b) Electronics with Microwave Engineering

(c) Electronics with Microelectronics

(d) Biotechnology

(e) Automotive Engineering

(f) Power Systems

(xix) Diploma in Forensic Science

6.6 School of Health & Pharmacy (SHAP)

(i) Bachelor of Pharmacy — B. Pharma

(ii) Bachelors in Hospital Management

(iii) Bachelors in Human Nutrition

(iv) Bachelors in Medical Laboratory Technology

(v) Bachelors in Occupational Therapy

(vi)	Bachelors in Physiotherapy	
(vii)	Bachelors in Radiology & Imaging Technology	
(viii)	Master of Pharmacy	M. Pharma
(ix)	Diploma in Health Care & Service	
(x)	Diploma in Nutrition & Dietetics	
(xi)	Diploma in Pharma Sales Management	
(xii)	Diploma in Health Information Technology	
(xiii)	Diploma in Pharmacy	
(xiv)	Diploma in Health Care Systems & Services Management	
(xv)	Diploma in General Nursing & mid wifery	D.G.N.M.
(xvi)	Bachelor of Nursing	B.Sc. (Nur.)
(xvii)	Master of Nursing	M. Sc. (Nur.)

6.7 School of Computer & Applied Software Engineering (SCASE)

(i)	Bachelor of Technology	B. Tech
	(a) Computational Management	
	(b) Internet Computing	
	(c) Computer Science & Engineering	
	(d) Mobile Computing	
	(e) Software Engineering	
(ii)	Bachelors of Computer Application	BCA
(iii)	Masters of Computer Application	MCA
(iv)	5 years Integrated MCA programme	
(v)	Master of Technology in Software Engg.	M. Tech (SE)
(vi)	Master of Technology	M. Tech
	(a) Computer Science & Engineering	
	(b) Intelligent Systems	
	(c) Parallel & Distributed Computing	
(vii)	Diploma in Computing	

(viii) Diploma in Information Technology

(ix) Diploma in Software Engineering

6.8 School of Hospitality & Tourism (SHoT)

(i) Bachelor of Arts B.A.

(a) Aviation / Cruise Hospitality Mgmt,

(b) Culinary Arts

(c) Hospitality and Hotel Administration

(d) Travel and Leisure Management

(ii) Bachelors of Arts Honours in International Hospitality Management

(iii) Master of Business Administration MBA

(a) Hospitality Management

(b) Tourism and Leisure Management

(iv) Diploma in Bakery & Confectionery

(v) Diploma in Cruise Hospitality Management

(vi) Diploma in Food & Beverage Management

(vii) Diploma in Front Office Management

(viii) Diploma in Hospitality Customer Relations

(ix) Diploma in Hospitality Management

(x) Diploma in Indian Regional Cuisine

(xi) Diploma in Institutional Catering

(xii) Diploma in Institutional Housekeeping

(xiii) Diploma in International Cuisine

(xiv) Diploma in International Ticketing and CRS

(xv) Diploma in Restaurant & Bar Management

(xvi) Diploma in Aviation Hospitality Management

(xvii) Diploma in Travel & Tourism

(xviii) Diploma in Culinary Arts (Advanced Diploma)

(xix) PG Diploma in Hospitality & Tourism

6.9 School of Insurance & Risk Management Studies (SIRMS)

(i) Bachelor in Insurance & Risk Management BIRM

(ii) Bachelor in Insurance Management

(iii) Masters of Arts in Insurance & Risk Management MA(IRM)

(iv) Masters in Life Insurance

(v) Master in General Insurance

(vi) Masters in Actuarial Applications

(vii) Doctoral Programme

6.10 School of Media & Communication (SMC)

(i) Bachelor of Arts in Advertising & Public Relation BA (Ad & Pr)

(ii) Bachelor in Journalism & Mass Comm. BJMC

(iii) Bachelor in Journalism & Media Studies BJMS

(iv) Diploma in Advertising Management

(v) Diploma in Journalism & Mass Communication

(vi) Diploma in Media Journalism

(vii) Diploma in Radio Anchoring & Audio Management

(viii) Diploma in TV Anchoring, News-reading & Broadcast Reporting

6.11 School of Design Engineering & Architecture (SDEA)

(i) Bachelor of Architecture B. Arch

(ii) Bachelor of Architectural Technology & Construction

(iii) Bachelors in Interior Design

(iv) Bachelors in Product Design.

(v) Bachelor in Building Services

(vi) Bachelor in Estate Management

(vii) Master of Architecture M. Arch.

(viii) Doctorate Programme

(ix) Diploma in Product Design

(x) Diploma in Interior Design

6.12 School of Film & Television Technology (SoFTT)

(i) BA Animation & Computer Graphics

(ii) BA Film & TV Production

(iii) BA Radio Production

(iv) BA Still Photography

(v) BA Acting & Choreography

(vi) MA Animation & Computer Graphics

(vii) MA Art Direction

(viii) MA Costume Design

(ix) MA Development Communication

(x) MA Film & TV Production

(xi) MA Media Management

(xii) MA Radio Production

(xiii) MA Still Photography

(xiv) MA Video Editing

(xv) MA Videography

(xvi) MA Cinema Studies

(xvii) MA Cinematography

(xviii) Diploma in Film & Television

(xix) Diploma in Moving Image

(xx) Diploma in Non-Linear Editing

(xxi) Diploma in Photo Journalism

(xxii) Diploma in Script-writing for Film & TV

(xxiii) Diploma in Acting & Choreography

(xxiv) PG Diploma in Animation & Multimedia

(xxv) PG Diploma in Multimedia Design & Management

6.13 BLS School of Business (BSoB)

(i) MBA Integrated (BBA + MBA)

(ii) MBA

(iii) MBA- Global Financial Management

(iv) MBA – International Business Administration

(v) MBA with Business & Finance

(vi) MBA with Business & Marketing

(vii) MBA with Interior Design

(viii) MBA with Media Studies

(ix) MBA with Tourism

(x) MBA with Advertising

(xi) MBA with Enterpreneurship

(xii) Executive MBA

(xiii) Executive Doctorate

(xiv) PGDBM

(xv) PG Diploma in Business Enterprise

(xvi) PG Diploma in Business Management

(xvii) PG Diploma in Enterpreneurship

(xviii) PG Diploma in International Business Management

6.14 BLS Media Studies (BMS)

(i) MA Advertising, PR & Corporate Communication

(ii) MA Brand Communication

(iii) MA Communication, Culture & Media

(iv) MA Marketing Communication

(v) Master in Journalism MJ

(vi) Masters in Mass Communication MMC

(vii) PGDMC – Mss Communication

(viii) Diploma in Advanced Reporting

(ix) Diploma in Advt., Public Relations & Corporate Comm.

(x) Diploma in Brand Management

(xi) Diploma in Cultural Studies

(xii) Diploma in Print, Electronic & Cyber Journalism (Hindi/English)

(xiii) Diploma in Rural Communication

(xiv) Diploma in Technical Writing

(xv) Diploma in Web Journalism

(xvi) Diploma in Web Journalism

(xvii) Doctoral Programmes

6.15 School of Arts & Management Science [illegible] (SAMSS)

(i) BBA

(ii) BBA- IT

(iii) BBA Accounting & Finance

(iv) BBA Human Resources

(v) BBA International Business Administration

(vi) BBA Marketing

(vii) BBA with Enterpreneurship

(viii) Diploma in Business

(ix) Diploma in Financial Management

(x) Diploma in Human Resource Management

(xi) Diploma in Sales & Marketing Management

6.16 School of Ancient Vedic Studies (SAVeS)

(i) B. Sc. Vedic Sciences

(ii) B.Sc. Universal Religion

(iii) Bachelor of Philosophy

(iv) Diploma in Vedic Astrology

(v) Diploma in Vedic Sciences

(vi) PG Diploma in Vedic Astrology

(vii) PG Diploma in Vedic Science, Philosophy and Management

(viii) Doctoral Programmes in Vedic Astrology

(ix) Doctoral Programmes in Vedic Sciences, Philosophy and Management

6.17 School of Fashion (SoF)

(i) BA Beauty Care & Health Services

(ii) BA (Hons) Fashion Design & Retail Management

(iii) BA (Hons) Fashion Design for Industry

(iv) BA (Hons.) Fashion Management

(v) BA (Hons.) Fashion Marketing & Promotion

(vi) BA (Hons.) Textile Design

(vii) BA Fashion & Apparel Design

(viii) MA Apparel Production, Quality Control

(ix) MA Costume Design

(x) MA Fashion Accessory Design & Technology

(xi) MA Fashion Industry

(xii) MA Fashion Styling & Photography

(xiii) MA Product Design & Dev. For Fashion Industry

(xiv) MA Textile & Fashion Design Management

(xv) MA Textile Design

(xvi) MA Fashion Portfolio Development

(xvii) MA Fashion Development

6.18 School of Performing Arts & Creative Education (SPACES)

(i) BA Graphic Design

(ii) BA Museology

(iii) Bachelors in Dance

(iv) BFA Painting

(v) BFA Print Making

(vi) BFA Sculpture

(vii) Bachelor of Performing Arts BPA

(viii) MA Graphic Design

(ix) MA Conservation

(x) MA Museology

(xi) MA Visual Research

(xii) MFA (Print Making/ Painting/Sculpture)

(xiii) MFA Critical Curation

(xiv) MFA Critical History of Art

(xv) MFA Museum & Heritage Exhibition Design

(xvi) Diploma in Guitar/Piano/Violin

(xvii) Diploma in Fine Arts

(xviii) Diploma in Art Appreciation

(xix) Diploma in Graphic Design

(xx) Diploma in Kathak

(xxi) Diploma in Music Appreciation

(xxii) Diploma in Tabla / Pakhawaj/ Sitar/Vocal

(xxiii) Diploma in Western Vocal/ Hindustani Vocal

(xxiv) Doctoral Programmes

6.19 BLS School of Dental Sciences (BSDS)

(i)	Bachelor of Dental Surgery	B.D.S.
(ii)	Masters of Dental Surgery	MD.S.

(iii) Diploma in Oral Surgery

(iv) Diploma in Orthodontics

(v) Diploma in Prosthodontics

(vi) Diploma in Conservation Dentistry

(vii) Diploma in Oral Pathology

7. The University may establish as many additional subjects/courses imparting educating in specified fields as may be necessary to meet the requirements emerging through new areas of studies.

8. The programmes/ courses in which approval of specific regulatory body or council is required will be offered after getting such approval/ permission.

9. The nomenclature of the degree shall be approved by the U.G.C. In case of differences of nomenclature, the degree shall be introduced after approval by the U.G.C.

ORDINANCE NO. 4

The Conditions of The Award of Fellowships and Scholarships
(Section 27 (1) (d) of the Adhiniyam)

1. Every year the University shall invite application through notifications for the awards to be made for Fellowships, Scholarships and students Scholarships.

2. Subject to the general conditions applicable to all Fellowships and Research Scholarships as laid down in paragraph 4 below, the value, duration and conditions for the award of University Grants Commission Fellowships shall be such as are laid down by the University Grants Commission.

3. The value and duration of Scholarships/Fellowships Instituted by the University shall be laid down by the Academic Council and approved by the Board of Management. The Selection of the candidate shall be made in accordance with the regulations laid down by the Board of Management from time to time.

4. Graduate and Postgraduate scholarships instituted by the University shall ordinarily be tenable for two academic sessions i.e. twelve months in the first year and ten months in the second year on condition that the scholarship holder produces a certificate of efficiency in studies from the Head of the Department in the subject of study.

5. The scholarship shall be tenable from the 01st of August if the scholarship holder joins the course within one month of the date of the opening of the college after the summer vacation and pays the tuition fee from the commencement of the session. In any other case, it shall be tenable from the date on which the candidate joins the course.

6. A scholarship shall be withdrawn in the subsequent year if the scholarship holder fails to secure at least 70% marks in the Previous Examination of the concerned course.

7. If a scholarship- holder is unable to appear at the previous examination on account of sickness or any other reasonable cause, the scholarship shall be paid only if the Head of the Institution certifies that the scholar diligently studied for the examination but was unable to take the examination for reasons beyond the control. Such a scholar shall not receive scholarship during the next session but shall be entitled to the scholarship for the subsequent year if the scholar passes the previous examination with the requisite standard in the succeeding year in the first attempt.

8. A scholarship – holder shall at all times be of good behavior and observe the code of conduct.

9. (A) A Scholarship shall be liable to termination, if-

   (i) The scholarship-holder discontinues studies during the middle of the session or.

(ii) The scholarship-holder after he has been given a reasonable opportunity to explain his conduct is in the opinion of the Academic Council guilty of a breach of para 8 of this ordinance and if the Academic Council to directs, the scholarship-holder shall also be liable to refund the amount of scholarship drawn by him.

(B) The order of termination passed by the Academic Council shall be final.

ORDINANCE NO. – 5

Conduct of Examination

(Section 27 (1) (e) of the Adhiniyam)

Definitions

"University Student" means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any program of study at the University at Main Campus and Satellite Campuses any institute of the University, Study Centres, Academic Centres and Colleges affiliated to the University.

"Regular Candidate" means a student who has pursued the course of study in a school/ college or a Academic Centres seeks to take examination of the University as such.

Methods of Computing the Attendance

(a) Attendance at lectures delivered and practicals / clinicals / sessionals if any, held during the academic session shall be counted.

(b) Attendance at N.C.C./ N.S.S. Camp, outdoor assignments, etc. during the session shall be taken as full attendance at lectures / practicals on each such day of the camp and / or assignments and the days of journey to such camp/assignments.

(c) Participation as a member of the University team in any Inter University competition shall be taken as full attendance for the day of participation in such competition.

(d) For special reasons such as prolonged illness, deficiency in percentage of attendance not exceeding fifteen percent of the total number of lectures delivered and practicals/ clinicals / sessionals held in each subject may be condoned by the Vice –Chancellor.

1. The students evaluation for award of all degrees/diplomas/certificates comprises the following.

   (a) Assignments

   (b) Mid- Semester examination

   (c) End-Semester examination

2. The weightage for the foregoing shall be as prescribed for each discipline and approved by the Academic Council.

3. Assignments

(a) The issue, submission and evaluation of assignments will be the responsibility of the Deans of respective colleges/schools. He shall maintain complete honesty in preparation and evaluation of the assignments.

(b) The entire class shall be divided in groups.

(c) Each group will be given a separate assignment with minimum commonality.

(d) A minimum of two assignments per subject per semester will be given to the students.

(e) Each student will be required to defend his assignment after submission through a process of presentation/viva-voce.

(f) Assignments will be prepared as per a standard format, approved by the Academic Council from time to time specific to colleges and schools.

(g) Students will be required to submit the assignments within two weeks from the date of issue.

(h) Assignments submitted after the due date will not be assessed for more than 50% marks.

4. Mid- Semester Examination

(a) Mid-semester examination shall be the responsibility of the Dean of respective College/School. He shall maintain total academic honesty in the conduct of these examinations.

(b) The mid-semester examination shall be held after a minimum of 45 days of formal teaching.

(c) The mid-semester examination shall be for a duration of not more than two hours and not less than one and half hours.

(d) The Practical examinations, where applicable, shall be held and be given a weightage as per the directions of the Academic Council.

(e) The mid-semester examination shall be held in the same manner as the end-semester examination

5. Results of Assignment and Mid-Semester Examination

The result of assignments and mid-semester examination shall be submitted to the Controller of Examinations (Deputy Registrar – Examinations) at least one week before the commencement of End-semester examination.

6. End-semester Examination

All arrangements for the conduct of end-semester examination shall be made

by the Controller of Examinations (sub-Registrar Evaluation) in accordance with such directions as may be issued by the Board of Management in consultation with the Academic Council.

7. The Controller of Examinations shall prepare and duly publish a programme for the conduct of examination specifying the date of each examination and last date by which applications and fees examination shall be paid by the intending examinees.

8. The Board of Management shall determine in consultation with the Academic Council the centers of examination in accordance with the provisions of the Adhiniyam and the Controller of Examination shall in consultation with the Institutions, which have been declared as examination centers, appoint. Superintendent and Assistant Superintendents, (if any) for each examination center and shall issue instructions for their guidance.

   Provided that for the purpose of appointment of an Assistant Superintendent at a center, the minimum strength of examinees appearing there-from shall be at least 300.

   a. The Superintendent of the Examination at each center shall be personally responsible for the safe custody of question papers and the answer-books sent to him and shall render to the University office a complete account of used and unused papers and answer books.

   b. The Superintendent shall supervise the work of invigilators working under him.

9. The University may change the examination centre of the examination any time if it deems proper without assigning any reason.

10. The Controller of Examination may on the recommendation of the Centre Superintendent appoint and amanuensis to write down dictation pertaining to answers to questions during an examination on behalf of an examinee who is unable to write himself/herself if he/ she is medically handicapped and possess a certificate of a Government Medical Officer, provided that such an amanuensis shall be a man/woman possessing qualification of at least one class lower than that of the examinee concerned.

11. The University may from time to time appoint inspectors or Board of Inspectors to see that the examinations are conducted strictly in accordance with procedures laid down. In the event of the Inspector pointing out a breach of procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the centre, and if any such action is taken a report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.

12. The Vice-Chancellor may cancel and examination at all centers if he is satisfied that there has been leakage of question papers or any other irregularity which in his opinion warrants such a step and report the action taken at the next meeting of Board of Management.

13. The Board of Management in consultation with the Academic Council may

issue such general instruction for the guidance of the Examiners, Centre Superintendents, Tabulators, Collators as it considers necessary for the proper discharge of their duties.

14. If a candidate has any communication to make on the subject of his/ her examination paper, it shall be made in writing to the Controller of Examination directly.

15. Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his/her examination, the matter shall be reported to the Controller of Examination who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.

16. Except as otherwise decided by the Board of Management, the examination answer-books and the foil and counter foil of the marks obtained by the examinees except the tabulated results, shall be destroyed or otherwise disposed of after 6 months from the date of the declaration of the results of the examination provided that the evaluated answer books of revaluation shall be destroyed/disposed of only after 3 months of the declaration of the revaluation result.

17. The Controller of Examination shall publish the combined results of the University examination on the notice board of the office of the University in addition to the Internet. The result when published shall simultaneously be communicated to the institutions concerned.

18. The remuneration of the examiners, Superintendents, Assistant Superintendents, Invigilators, Tabulators and collators and the deductions to be made in the remuneration for errors noticed shall be such as prescribed from time to time by the Board Management.

19. Where a student applies for revaluation, the answer books of the subjects in which the revaluation is sought will be sent to an examiner other than the one who evaluated it initially. The examiner so appointed will check and evaluate only those questions, which have been left unmarked. He will also check the total. The answer book will not be re-evaluated for already evaluated questions.

Provided that such an examiner will receive a remuneration as prescribed by the Board of Management.

20. (1) No ex-student candidate shall be admitted to an examination of the University unless he submits with his application the following :

(i) The Statement of marks (in original) obtained by his as a regular candidate at the said examination issued by the University together with an attested copy thereof, or

(ii) In case he was duly admitted to the said examination as a regular candidate but he could not appear thereat, a certificate from the institute last attended by his showing the year, the roll number and the examination to which he was admitted as a regular candidate.

(2) Every ex-student candidate shall appear at the Examination Centre at which he appeared as regular candidate.

21. No Candidate shall appear, in more than one-degree examination or in more than one subject for the Master's degree in one and the same year.

22. (1) A candidate who has passed first year of Bachelor's degree, examination or Master's degree examination of another University/ Awarding Body, (Indian or Foreign) may be admitted to the next higher examination of the University for the corresponding degree subject to such conditions as laid down by the Academic Council from time to time.

Provided at least 75% of the courseware offered by the University/ Awarding Body of the candidate match with the courseware of the University for the award of the corresponding degree. Provided that the student shall have to secure at least the pass grades in the bridge modules.

23. No person who has been expelled or rusticated from any college or University or has been debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the sentence is in operation.

24. An application for admission to an examination received by the Controller of Examination after the last date notified by the University but not later than fifteen days after such last date may be entertained on payment of a last fee as prescribed from time to time.

Provided that the candidate will be required to secure at least pass grades in the Bridge Modules.

23. No person who has been expelled or rusticated from any college or University or has been debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the sentence is in operation.

24. An application for admission to an examination received by the Controller of Examination after the last date notified by the University but not later than fifteen days after such last date may be entertained on payment of a last fee as prescribed from time to time.

25. Not withstanding anything contained in the Ordinance relating to admission of candidates to an examination of the University, the Vice-Chancellor may, in special cases in which he is satisfied that the delay in submitting the application for admission to an examination is not due to lack or negligence on the part of the candidate and that it would be a great hardship to the candidate if his application is rejected, allow an application which is otherwise complete in all respects to be entertained with the late fee prescribed by the Board of Management from time to time even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in the foregoing paragraph.

26. (1) The controller of Examination shall issue an admission card in favour

of a candidates if :-

(a) The application of the candidate is complete in all respects.

(b) The fees as prescribed have been paid by the candidate.

(c) The assignments have been submitted.

(d) The attendance is more than 60%.

(e) The student has scored a minimum of 50% marks is assignments and mid-semester collectively.

(2) Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

(3) The admission card issued in favour of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that :-

(a) The admission card was issued by mistake, or the candidate was not eligible to appear in the examination.

(b) Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in or with the application for enrolment, admission to the institute, college or school are false or incorrect.

(4) The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, grant a duplicate admission card on the payment of a fee prescribed. Such a card shall show in a prominent place to the word "Duplicate".

27. (1) A candidate who due to sickness or other cause is unable to present himself/herself at an examination, shall not receive a refund of his fee.

Provided that the Vice-Chancellor may, in case in which he is satisfied about the genuineness or merit of it, order for adjustment of the following portion of the fee towards the next immediate examination viz.

(j) Examination fee after deduction of 10% fee paid.

(ii) Fee for statement of marks.

Other fees paid by the candidate shall lapse to the University. Application for such adjustment from a candidate accompanied by a Medical Certificate of illness if applicable, must be sent so as to reach the Controller of Examination not later than 30 days from the date of commencement of the examination at which the candidate was to appear.

(2) The fees paid by a regular candidate who is debarred from appearing at an examination due to shortage in attendance at lectures/particulars, may be refunded after deduction of service charges of 10%.

(3) Examination and other fees of a candidate whose application for appearing at an examination has been rejected for some reason or he could not furnish his form within the prescribed date; necessary fees having been paid in the University account, may be refunded after deduction of service dharges of 10%.

(4) The examination and marks statement fee of a candidate who dies before appearing at the examination may be refunded in full to his guardian or his successor.

(5) The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an examination is cancelled on account of producing fraudulent documents or giving false particulars shall stand forfeited.

28. (1) Any candidate, who has appeared at an examination conducted by the University, may apply to the Controller of Examination for the scrutiny of his marks in the answer scripts of theory papers in any subject and rechecking of his results. Such application must be made so as to reach the Controller of examination within 15 days of the publication of the result of the examination.

(2) Such application must be accompanied by fee as per schedule given below –

(a) In one subject Rs. 200/-

(b) In all subject Rs. 1000/-

(3) A candidate shall not be entitled to a refund of the fee.

(4) The result of scrutiny shall be communicated to the candidate.

(5) If as a result of scrutiny, if is found that the examination should be declared as having passed or placed in a higher division, the result of the candidate shall be revised accordingly.

29. Duplicate copies of the following certificate shall be granted on payment of the fee mentioned against each viz.

(i) Statement of Marks Rs. 150/-

(ii) Migration certificate Rs. 300/-

(iii) Provisional Certificate Rs. 500/-

(iv) Degree Certificate Rs. 1500/-

Provided further, the duplicate copy of the Migration Certificate, Degree, Diploma shall not be granted except in cases in which the Vice-Chancellor is satisfied by the production of an affidavit on a stamped paper or proper value required by law for the time being in force that the applicant has not utilized the original documents for appearing at an examination and has lost the same or that the same has been destroyed and that the applicant really need a duplicate copy. Duplicate copy shall be issued only once.

30. The names of the first ten successful candidate in each final Degree Examination other than supplementary examination who obtain first division shall be declared in order of Merit.

31. Not withstanding anything contained in the concerned ordinance and examinee who has appeared in all the theory papers, practicals, viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester examination in 1st attempt and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects in any of the Graduate examinations but secures more than the minimum aggregate marks required, may be given a grace of upto five marks with not more than three marks given in any one subject to enable him to pass the examination. These marks shall, however, not be counted towards the total.

32. The Vice-Chancellor may award one grace mark in case the candidate is missing a division by one mark. Where the deficiency is so condoned one mark shall not be added to the total.

33. (1) The following shall be eligible to appear at supplementary examination.

(a) Candidates who have failed at any B.A, B.Sc., or B.Com examination in not more than two subjects.

(b) Candidate for examination other than those enumerated in (a) above who are declared eligible to appear at a supplementary examination in accordance with the provisions of the examination in accordance with the provisions of the respective examination Ordinance.

(2) In the case of subject for supplementary examination on which there is also a practical test, a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical and in practical only if he has passes in the written papers. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both the parts of the subject.

(3) Except when provided otherwise in the Ordinance concerned a candidate who has been declared eligible for a supplementary examination may appear as supplementary examination candidate in the two examinations immediately following the examination in which he was declared to be so eligible and thereafter he shall be required to appear in all the papers at the next examination.

(4) A candidate appearing in the supplementary examination shall be declared to have passed the examination if he secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be except when provided otherwise in the examination Ordinance concerned. The marks obtained by the candidate in the supplementary/examination shall taken into account in determining the division at the examination.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक 2134/प्र. 1/अविअ/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	डुन्डेरा	0.42	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग क्रमांक-2 (भ+स), दुर्ग.	उतई, उमरपोटी डुन्डेरा सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/ 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खरसिया	0.065	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/ 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	रतनमहका	0.040	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/ 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटेमुडपार	0.441	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/ 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	करपीपाली	1.204	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/ 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	करूमौहा	0.024	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	डडाईडीह प.ह.नं. 38	0.081	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बैगामुड़ा जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कांटाहरदी प.ह.नं. 7	1.469	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रायगढ़.	बरदापुटी शाखा नटवरपुर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2003

क्रमांक भू-अर्जन/40 अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जोरा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.832 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	76/2	0.024
	100/2	0.056
	100/3	0.016
	76/12	0.024
	101, 1194	0.028
	95/2	0.032
	95/6	0.032
	96	0.012
	97	0.068
	98	0.056
	99/1	0.028
	99/2	0.004
	86	0.120
	60	0.088
	61	0.088
	51/1	0.068
	52	0.088
योग	17	0.832

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ''सरमंदी'' जोंक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2003

क्रमांक भू-अर्जन/41 अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.406 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.070
2	0.024
44, 45	0.048
3/3	0.028
48/3	0.024

	(1)	(2)
	4/1	0.038
	5/1	0.012
	43/1	0.030
	42/2	0.028
	46/1	0.012
	46/2	0.012
	46/3	0.016
	46/4	0.018
	47/2	0.046
योग	14	0.406

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- "सरमंदी" जोंक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2003

क्रमांक भू-अर्जन/42 अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-खपरीडीह, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.175 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23	0.077
20	0.049
128	0.012
968/1	0.008
916	0.021
12	0.308
13	0.020
130	0.053
120	0.036
893	0.020
14	0.065
115	0.016
116	0.022
15	0.056
19/1	0.012
22/2	0.036
100	0.195
101/1	0.033
104/1	0.049
105	0.036
866	0.056
106	0.036
107	0.024
863	0.028
108	0.016
972	0.012
109	0.016
978	0.041
348	0.032
974	0.028
801	0.020
131	0.020
117	0.008
118/1	0.012
119	0.041
231/1	0.036
349	0.013
233	0.012
222 1302 } 2	0.053

(1)	(2)
222	0.061
221/2	0.065
339/1	0.032
850	0.008
339/2	0.032
336/2	0.064
970/2	0.041
342/1, 2	0.049
343	0.033
344	0.008
377	0.049
378	0.041
911	0.041
379	0.009
901/3, 902/3, 921/3	0.033
375	0.010
376	0.059
394/1, 2, 3, 4, 5	0.041
964/1	0.004
972	0.012
973	0.040
964/2	0.036
965	0.041
966	0.041
967	0.008
968/2	0.028
994	0.041
912	0.025
914/1	0.057
997/1	0.036
915	0.021
918	0.004
919	0.033
920	0.004
892/3	0.049
892/4	0.009
896, 897 | 2	0.012
861/1	0.041
861/2	0.041
802	0.009
862	0.020
864	0.041
865	0.052
796/1	0.009
797/3	0.012
796/2	0.012
796/3	0.012
797/2	0.012
796/4	0.012
796/6	0.012
336/1, 336/5	0.061
979	0.008
336/3	0.016
योग 93	3.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खपरीडीह शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 152/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-कसही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
323/2	1.37
347/2	0.16
369	0.05
313	0.15
370	0.10
267	0.20
264	0.02
योग 7	2.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 153/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
902	0.05
903	0.06
936	0.06
914	0.07
917	0.03
918	0.03
931	0.07
932	0.08
933	0.06
934/1	0.06
942	0.04
941	0.02
946/2	0.16
946/1	0.05
980/1	0.07
959	0.20
योग 16	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 155/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
892/1, 892/2	0.25
893	0.36
894	0.43
895	1.33
896	0.06
917	1.07
920	0.06
921	0.62
935	0.40
936	0.30
940	0.30
938	0.08
923	0.25
924	0.28
925	0.07
926	0.07
928	0.38
929	0.28
930	0.17
942	0.14
943	0.16
892/2	0.30
916	0.14
योग 24	7.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 154/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-डुंडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
364/1	0.17
364/3	0.20
574/2	0.13
609/1	0.24
610	0.23
388	0.68
567	0.17
389	0.47

(1)	(2)	(1)	(2)
391	0.80	574/1	0.13
392	0.35	598	0.29
421	0.16	510	0.26
420/3	0.40	514	0.12
584	0.06	568	0.62
420/2	0.20	572	0.10
423/1	0.10	570	0.13
604	1.71	603	0.40
422	0.26	571	0.24
479	0.07	573	1.04
447	0.06	575/1	0.10
450	0.09	575/2	0.37
451/2	0.06	576	0.83
451/3	0.04	577	0.40
452	0.15	580/1	0.32
478	0.20	580/2	0.41
513	0.31	580/3	0.41
480	0.48	580/4	0.08
481	0.15	599/1	0.28
482	0.18	599/6	0.18
483	0.41	599/2	0.28
506	0.23	599/5	0.10
597	0.30	599/3	0.27
484	0.26	599/4	0.12
485	0.25	600/1	1.11
507	0.29	600/2	0.57
486	0.27	601	0.46
487	0.23	602	0.28
569	0.38	605	0.25
566	0.19	606	0.29
488	0.18	607	0.18
489	0.23	608	0.52
507	0.15	609/2	0.20
491	0.15	613	0.49
499	0.39	623	3.35
512	0.64	634/1	0.31
511	0.30	634/2	0.12
515	0.12	634/3	0.20
501	0.23	635/1	0.15
509	0.29	635/2	0.15
508	0.63	635/3	0.15
		योग 90	30.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.